भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1086

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

पीएमआईएस के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां

1086. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री राजेश वर्माः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्नातक और शोध छात्रों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) व्यावसायिक विकास को बढाने के लिए लागू की गई 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' (पीएमआईएस) का ब्यौरा क्या है;
(ग) कंपनियों के साथ इंटर्न के प्रारंभिक मिलान के अलावा योजना की प्रभावशीलता को मापने का क्या तरीका है;
(घ) महाराष्ट्र जैसे कम औद्योगिक राज्यों में इंटर्नशिप प्लेसमेंट को लागू करने में क्या विशिष्ट चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा उन्हें कैसे कम किया जाएगा;
(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी बजट राशि का उपयोग किए जाने की आशा है; और
(च) इस योजना के संभावित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): पूर्व-स्नातकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) लागू कर रहा है जिसमें तीन घटक योजनाएं हैं, अर्थात् (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय सेक्टर योजना (सीएसएसएस); (ii) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एसएसएस); (iii) केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)। ये योजनाएं सभी छात्रों को शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए समान अवसर प्रदान करती हैं और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी 06.11.2024 को शुरू की गई थी ताकि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों के मेधावी छात्रों को ट्यूशन फीस और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त शैक्षिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3% ब्याज अनुदान भी अधिस्थगन (मोरेटोरियम) अवधि के दौरान प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी ठोस अकादमिक नींव के साथ-साथ अनुसंधान घटक को शामिल करके पूर्व-स्नातकों और अनुसंधान अध्येताओं की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो छात्रों को मौखिक और लिखित सम्प्रेषण कौशलों के साथ-साथ स्वतंत्र क्रांतिक सोच कौशलों का विकास करने में समर्थ बनाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने अनुमोदित संस्थानों में विद्यार्थियों और संकाय के लिए तकनीकी शिक्षा में वृद्धि करने हेतु विभिन्न योजनाओं को भी बढ़ावा दिया।

(ख): बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। पीएम इंटर्नशिप योजना इंटर्न को व्यवसायों या संगठनों के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करती है जो शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, बदले में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम-पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देश www.pminternship.mca.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना-प्रायोगिक परियोजना के दिशा-निर्देशों में महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में योजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और अन्य पहलुओं की निगरानी के लिए एक निगरानी और संचालन समिति के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिणामों का पता लगाने के लिए एक समवर्ती निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम (एमईएल) ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने आईआईएम बैंगलोर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सहयोग से इसके कार्यान्वयन के जारी रहते हुए विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया एकत्र करने और प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है।

(ङ): योजना की प्रायोगिक परियोजना के लिए, 840 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(च): आज की तारीख तक, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों द्वारा 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए गए हैं। इसकी तुलना में, लगभग 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और कंपनियों द्वारा चयन की प्रक्रिया चल रही है

*****